भाग एक : अर्थव्यवस्था - समीक्षा और संभावनाएं

I मूल्यांकन और संभावनाएं

I.1 वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता कम हो गई है और मार्च 2023 में कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में वित्तीय स्थिरता के लिए बैंकों की विफलता से उत्पन्न जोखिम कम हो गया है। दृढ़ नीतिगत कार्रवाइयों ने अभी के लिए आत्मविश्वास बनाये रखा है। जो असहज शांति बनी हुई है, उसके बीच वैश्विक आर्थिक संभावनाओं का पुनर्मूल्यांकन चल रहा है। 2022 में कई और अक्सर अतिव्यापी आघातों, जैसे कि यूक्रेन युद्ध; खाद्य और ऊर्जा मुद्रास्फीति में लगातार वृद्धि; और दुनिया भर में आक्रामक और समकालिक मौद्रिक नीति सख्त होने के परिणामस्वरूप बनी तंग वित्तीय स्थितियों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था द्वारा समुत्थानशीलता प्रदर्शित करने के बाद उपलब्ध अनुमान 2023 और 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के संबंध में एक कमजोर संभावना का संकेत देते हैं। सबसे कमजोर देश बड़े कर्ज़ के बोझ से दबे हुए थे। 2023 के शुरुआती महीनों में पण्य कीमतों में गिरावट और आपूर्ति शृंखलाओं के क्रमिक सामान्यीकरण के कारण मुद्रास्फीति पर युद्ध-प्रेरित कुछ दबाव कम हो गए हैं। इसके बावजूद वैश्विक अवस्फीति की गति अपेक्षा से कम बनी हुई है। वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन को अनिवार्य रूप से फिर से परखा जाएगा जब अति सुलभ चलनिधि समाप्त हो जाएगी और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंक अपने विस्तारित तुलनपत्रों को संकुचित कर देंगे। मार्च में बैंकिंग प्रणाली पर पड़े दबाव के दौर से सबक लेते हुए कई देशों में वित्त संबंधी विनियामकीय नीतियों का सख़्त होना तय है।

I.2 इस बीच, गंभीर स्वरूप की संरचनात्मक ताकतें काम कर रही हैं जो मध्यम से दीर्घकालिक वैश्विक संभावनाओं को मौलिक रूप से आकार दे सकती हैं। व्यापार और पूंजी प्रवाह तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रभावित करने वाले गहन भू-आर्थिक बदलावों ने संवृद्धि में वैश्वीकरण के योगदान को कमजोर कर दिया है। अत्यधिक अनिश्चितता के माहौल में निजी निवेश कमजोर बना हुआ है। मुद्रास्फीति दबाव और वैश्विक व्यापार पर विभक्तिकरण का असर कुल उपभोग मांग को कम कर सकते है जो संवृद्धि की गति को धीमा करते है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अधिक आयु वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के कारण श्रम आपूर्ति की स्थिति बदल रही है। हरित परिवर्तन ने, जो एक सामान्य वैश्विक लक्ष्य है, नवीकरणीय और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में नए निवेश के अवसर खोले हैं, लेकिन कार्बन उत्सर्जन को कम करने की उच्च लागत विकास आकांक्षाओं को प्रभावित कर सकती है। डिजिटलीकरण भी संवृद्धि के नए अवसर प्रदान करता है, लेकिन प्रौद्योगिकी और साइबर नव-परिवर्तनों की लागत भी बढ़ रही है।

I.3 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के लिए परिदृश्य और भी अनिश्चित प्रतीत होता है क्योंकि वे एक साल के महामारी संकट, खाद्य और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और यहां तक कि उसकी कमी होने, धारण क्षमता से अधिक कर्ज़ होने और वैश्विक प्रभावों की बार-बार की घटनाओं से प्रभावित हैं, जिससे उनका पूंजी प्रवाह और सामान्यीकृत जोखिम बचाव अस्थिर हुआ। मध्यम अवधि में आगे देखते हैं तो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के जीवन स्तर के साथ अभिसरण की उनकी संभावनाओं को एक झटका लगा है, और साथ ही व्यापार और पूंजी प्रवाह के माध्यम से वैश्वीकरण के लाभ कम हो रहे हैं।

I.4 इस अशांत वैश्विक आर्थिक माहौल में भारत ने संवृद्धि की गति में लगातार तेजी के साथ समष्टि आर्थिक और वित्तीय

* : जहां संभव है, इस अध्याय में मार्च 2023 के बाद की अद्यतन जानकारी दी गई है।

स्थिरता का अनुभव किया है। यह एक मजबूत समष्टि आर्थिक नीति वातावरण और अर्थव्यवस्था के सहज लचीलेपन को दर्शाता है जिसने इसे वैश्विक आवर्ती आघातों के खिलाफ मजबूत किया है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है, जिसने पिछले पांच वर्षों के दौरान वैश्विक संवृद्धि में औसतन 12 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत किए गए प्रयासों और आपूर्ति प्रबंधन के संयुक्त प्रभाव के तहत मुद्रास्फीति अपने उच्च स्तर से कम होती जा रही है। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण से महामारी प्रेरित उच्च स्तर से ऋण और घाटे का स्तर कम होता जा रहा है। चालू खाता घाटा धारणीय स्तरों के भीतर बना हुआ है, और समष्टि आर्थिक स्थिरता स्थापित हो रही है। बैंकों, वित्तीय संस्थानों और कॉर्पोरेट संस्थाओं के मजबूत और स्वस्थ तुलनपत्र महामारी और युद्ध से नष्ट हुई संवृद्धि गति को फिर से हासिल करने में मदद कर रहे हैं। जनसांख्यिकीय लाभांश, डिजिटल क्रांति, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए नीतिगत पहल, सेवा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता के पुनरुत्थान और अनुकूल भू-आर्थिक स्थिति से मध्यम अवधि की संभावनाएं बेहतर हुई हैं।

2. 2022-23 के अनुभव का मूल्यांकन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

I.5 वैश्विक अर्थव्यवस्था 2022 की शुरुआत तक, बड़े नीतिगत प्रोत्साहन और व्यापक स्तर पर किए गए टीकाकरण की सहायता से, कोविड-19 महामारी की लगातार लहरों के प्रभाव से उबर रही थी, और उसी समय यूक्रेन में युद्ध ने उथल-पुथल मचा दी। महामारी के दौरान (2020 और 2021) किए गए ठोस राजकोषीय और मौद्रिक नीति हस्तक्षेप से जो लाभ हुए थे वे इस युद्ध के प्रभाव से कम हो गए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार वैश्विक मुद्रास्फीति में सामान्य वृद्धि ने केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीति के तहत ब्याज दर में लगातार वृद्धि करने और चलनिधि को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे, वित्तीय स्थितियां तंग हुईं, और अन्य कारकों के साथ-साथ, संवृद्धि पर असर पड़ा और वह 2022 में घटकर 3.4 प्रतिशत हो गयी जो 2021 में 6.2 प्रतिशत थी।

I.6 उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं पर वैश्विक प्रसार प्रभाव की लहरों के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर मुद्रा मूल्यह्रास हुआ, पूंजी का पलायन हुआ, निवेशकों की जोखिम से बचने की भावना बढ़ी और उनमें से कुछ में ऋण संकट बढ़ गया। उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के लिए उधारी लागत में बढ़ोतरी और जोखिम से बाहर रहने की भावनाओं के कारण साल के ज्यादातर समय बॉण्ड और इक्विटी बाजारों से निवेशों की निकासी हुई। वैश्विक मंदी के बढ़ते जोखिम ने समग्र समष्टि आर्थिक और वित्तीय संभावनाओं को धूमिल कर दिया। जारी किए गए आंकड़ों ने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं, दोनों में समुत्थानशील श्रम बाजारों और उपभोक्ता खर्च का संकेत देने पर वर्ष की दूसरी छमाही में मनोभावों में सुधार हुआ। अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में सॉवरेन बॉण्ड प्रतिफल में कमी आई और इक्विटी बाजारों ने खोई हुई स्थिति वापस पा ली। साल के अंत में अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में अन्य मुद्राओं को बढ़ावा मिला।

I.7 वर्ष के अंत में, यूरोप में अपेक्षा से कम ठंड पड़ने, बढ़ती ऊर्जा की कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए मिले नीतिगत समर्थन, लचीले श्रम बाजार और मुद्रास्फीति के नरम पड़ने के संकेतों से वैश्विक अर्थव्यवस्था बहाली के लिए तैयार हुई। महामारी प्रतिबंधों में ढील, आपूर्ति शृंखला में सुधार और रसद व्यवधानों को दूर करने, और संपर्क-गहन सेवाओं की मांग में उछाल ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद, वैश्विक मुद्रास्फीति, 2021 में 4.7 प्रतिशत से बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गई, जो वर्ष के दौरान अधिकांश देशों में लक्ष्यों से अधिक है। महामारी के बाद वैश्विक मांग में मंदी और यूक्रेन में युद्ध के कारण वस्तुओं और सेवाओं के सीमा पार आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण वैश्विक व्यापार (वस्तु एवं सेवा) संवृद्धि, जो 2021 में 10.4 प्रतिशत थी, 2022 में घटकर 5.1 प्रतिशत रह गई।

घरेलू अर्थव्यवस्था

I.8 कड़ी वैश्विक चुनौतियों के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2022-23 में वास्तविक जीडीपी में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किये जाने की संभावना है। विवेकाधीन खर्च में निरंतर सुधार, विशेष रूप से संपर्क गहन सेवाओं में सुधार, उपभोक्ता विश्वास की बहाली, कोविड-19 के कारण लगातार दो वर्षों के पृथकवास के बाद त्योहारी मौसम में उच्च खर्च और पूंजीगत व्यय पर सरकार के जोर ने विकास की गति को बल दिया। तथापि, वर्ष की दूसरी छमाही में प्रतिकूल आधार प्रभावों, मुद्रास्फीति उच्च रहने के कारण निजी उपभोग मांग कमजोर पड़ जाने, निर्यात वृद्धि में मंदी और इनपुट लागत पर निरंतर दबावों के कारण वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की गति कम हो गई।

I.9 2022-23 में कृषि और संबद्ध गतिविधियां समुत्थानशील थीं। योजित सकल मूल्य (जीवीए) में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। यद्यपि दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) के असमान स्थानिक और अस्थायी/कालगत वितरण के कारण *खरीफ* खाद्यान्न उत्पादन में मामूली गिरावट आई, फिर भी *खरीफ* तिलहन, गन्ना और कपास का उत्पादन वर्ष के दौरान अधिक था। मार्च 2023 में देश के कुछ हिस्सों में बेमौसम बारिश के कारण हुए कुछ नुकसान के बावजूद, अधिकांश फसलों के लिए *रबी* के एकड़ क्षेत्रफल में वर्ष के दौरान विस्तार हुआ और *रबी* फसल उत्पादन, खाद्यान्न और तिलहन दोनों की संभावनाएं आशाजनक बनी हुई हैं।

I.10 औद्योगिक क्षेत्र में, विनिर्माण गतिविधि ने वैश्विक प्रसार प्रभाव का सामना किया, जबकि बिजली उत्पादन ने मजबूत वृद्धि का प्रदर्शन किया, और खनन क्षेत्र ने स्थिर गतिविधि दर्ज की। निर्माण गतिविधियों की रफ्तार बनी रही, जबकि, बुनियादी ढांचे और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को बुनियादी ढांचे में सरकार की पहल वाले निवेश से लाभ हुआ। दूसरी ओर उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन सुस्त रहा और वाहन जैसे क्षेत्रों में सुधार एकतरफा रहा। खपत में असमान सुधार स्पष्ट था क्योंकि पैसेंजर कारों में सुधार की तुलना में मूल्य-संवेदी प्राथमिक स्तर के कार सेगमेंट में वृद्धि सुस्त हो गई थी। दोपहिया वाहनों की बिक्री, जिसमें ग्रामीण भारत की मांग 40 प्रतिशत है, में लगातार गिरावट भी ग्रामीण मांग में कमी का संकेत था।

I.11 कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारत ने भी 2022-23 के दौरान मुद्रास्फीति में वृद्धि का अनुभव किया, जो मुख्य रूप से अतिव्यापी वैश्विक आपूर्ति आघातों और उच्च इनपुट लागत के प्रभाव को दर्शाता है। कच्चे तेल, खाद्य, उर्वरकों और धातुओं की वैश्विक कीमतों में तेज वृद्धि के साथ-साथ युद्ध के बाद नए सिरे से आपूर्ति में व्यवधान ने वर्ष की पहली छमाही के दौरान व्यापक आधार पर मूल्य दबाव डाला। परिणामस्वरूप, अप्रैल 2022 में मुद्रास्फीति 7.8 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के दबाव के धीरे-धीरे सामान्य होने, वैश्विक पण्य कीमतों में नरमी आने, सरकार द्वारा लक्षित आपूर्ति प्रबंधन उपायों और रिज़र्व बैंक द्वारा नीतिगत रेपो दर में लगातार वृद्धि के बाद, मुद्रास्फीति वर्ष की दूसरी छमाही में कम हो गई। कुल मिलाकर, हेडलाइन मुद्रास्फीति, जो 2021-22 में 5.5 प्रतिशत थी, बढ़कर 2022-23 में 6.7 प्रतिशत हो गई। घरेलू मांग की स्थिति में सुधार के बीच वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों पर इनपुट लागत का देरी से प्रभाव पड़ने के कारण पहले से ही बढ़ी हुई मूल मुद्रास्फीति काफी स्थिर हुई, जो पूरे वर्ष लगभग 6.0 प्रतिशत पर रही।

I.12 यूक्रेन युद्ध के परिणामस्वरूप जब मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मौद्रिक नीति के संचालन में मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता दी। समिति ने अप्रैल 2022 में अपने रुख को बदल दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर लक्ष्य के भीतर रहे और साथ ही संवृद्धि को भी समर्थन मिले। मुद्रास्फीति मार्च 2022 में 7.0 प्रतिशत पर पहुंच गई थी, और एमपीसी ने अंदाज़ लगा लिया था कि और भू-राजनीतिक तनाव के बीच निकट भविष्य में मुद्रास्फीति दृष्टिकोण तेजी से बिगड़ जाएगा, एमपीसी ने मई 2022 में निर्धारित बैठकों से इतर आयोजित एक बैठक में नीतिगत रेपो दर को 40 बीपीएस बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत कर

दिया। एमपीसी ने 2022-23 के दौरान प्रत्येक बैठक में नीतिगत रेपो दर में वृद्धि की ताकि मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं को बनाए रखा जा सके, इसके परिणामस्वरूप होने वाले प्रभावों को नियंत्रित किया जा सके और मुद्रास्फीति संबंधी लक्ष्य के पास रखा जा सके। संचयी रूप से, एमपीसी ने अप्रैल 2022 में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) कॉरिडोर की निचली सीमा में 40 बीपीएस की वृद्धि के अलावा 2022-23 के दौरान नीतिगत रेपो दर को 4.00 प्रतिशत से 250 बीपीएस बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया। तदनुसार, एक दिवसीय भारित औसत मांग मुद्रा दर, जो मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य है, वर्ष के दौरान 320 बीपीएस बढ़ गया, जो पूरी तरह संचयी नीतिगत उपायों के अनुरूप रहा।

I.13 रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव के अनुरूप चलनिधि प्रबंधन के लिए सूक्ष्म और फुर्तीला दृष्टिकोण अपनाया, अर्थात, बैंक ने प्रणाली में उपलब्ध अधिशेष चलनिधि के आकार में क्रमिक रूप से कमी की, और साथ ही अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनिधि बनाए भी रखी। कुल मिलाकर, अधिशेष चलनिधि - जैसा कि एलएएफ़ के तहत अवशोषित शुद्ध राशि में परिलक्षित होता है - मार्च 2022 में 6.6 लाख करोड़ रुपये के दैनिक औसत से मार्च 2023 में 0.14 लाख करोड़ रुपये तक कम हो गयी।

I.14 2022-23 में, भू-राजनीतिक तनाव बढ़ जाने, अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि से आई आक्रामकता और वैश्विक संवृद्धि दृष्टिकोण के बिगड़ जाने से निवेशकों की धारणा प्रभावित होने से वित्तीय बाजारों को समय-समय पर अस्थिरता का सामना करना पड़ा। तथापि, निवेशों के बहिर्वाह और विदेशी मुद्रा बाजार के दबाव के बावजूद भारत में इक्विटी बाजारों में मामूली वृद्धि हुई, जो भारत में संवृद्धि की क्षमता और निवासी संस्थाओं द्वारा बाजार में बढ़ते निवेश को परिलक्षित करता है। 2022-23 के दौरान नीतिगत रेपो दर में वृद्धि और अधिशेष चलनिधि स्थिति में कमी के चलते मुद्रा बाजार ब्याज दरों में वृद्धि हुई। मौद्रिक नीति के तहत उठाए गए कदमों और बदलती मुद्रास्फीति-संवृद्धि संभावनाओं के अनुरूप ही सॉवरेन बॉण्ड प्रतिफल सख्त हो गया; हालांकि, एई में बॉण्ड प्रतिफल में देखी गई तेज वृद्धि की तुलना में यह वृद्धि नियंत्रित सीमा में रही। भू-राजनीतिक तनाव के कारण आर्थिक गिरावट, वैश्विक केंद्रीय बैंकों के आक्रामक मौद्रिक नीति रुख और मंदी की बढ़ती आशंकाओं का बाज़ार की भावनाओं पर असर पड़ने के कारण 2022-23 की पहली छमाही में घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। कंपनियों की मजबूत आय और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश से वे दूसरी छमाही की शुरुआत में सुधरे और 01 दिसंबर 2022 को सार्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुए। अमेरिका में कुछ विशिष्ट बैंकों के पतन के बाद वित्तीय स्थिरता जोखिमों के उभरने और यूरोप में एक प्रमुख वित्तीय सेवा प्रदाता के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में चिंताओं के बीच कमजोर वैश्विक संकेतों ने वर्ष के अंत में बाजारों में अस्थिरता उत्पन्न की। बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि में कमी, निरंतर उच्च ऋण वृद्धि और चुनिंदा क्षेत्रों में ऋण मूल्य निर्धारण के लिए अनिवार्य बाहरी बेंचमार्क व्यवस्था के कारण 2022-23 के दौरान ऋण बाजार में मौद्रिक संचरण – नीतिगत रेपो दर परिवर्तनों का प्रभाव उधार दरों पर पड़ने से -मजबूत हुआ।

I.15 सरकारी वित्त का प्रबंधन विवेकानुसार निर्देशित था। तदनुसार, केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) 2021-22 में जीडीपी के 6.75 प्रतिशत से घटकर 2022-23 (आरई)[1] में जीडीपी का 6.45 प्रतिशत हो गया, जो महामारी से संबंधित प्रोत्साहन की वापसी को परिलक्षित करता है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न उच्च खाद्य और ऊर्जा की कीमतों से बचाने के लिए लक्षित राजकोषीय उपाय

[1] 'बजट एट ए ग्लांस 2023-24' के अनुसार, सकल राजकोषीय घाटा, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, 2021-22 के 6.7 प्रतिशत से घटकर 2022-23 (संशोधित अनुमान) में 6.4 प्रतिशत हो गया, जो 2022-23 के लिए जीडीपी के पहले अग्रिम अनुमानों पर आधारित है। 2022-23 के लिए जीडीपी के दूसरे अग्रिम अनुमानों को ध्यान में रखते हुए, 2022-23 (संशोधित अनुमान) के लिए सकल राजकोषीय घाटा, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, 6.45 प्रतिशत होता है, जबकि केंद्रीय बजट 2023-24 में 6.43 प्रतिशत का संशोधित अनुमान लगाया गया था।

किए गए थे। सब्सिडी व्यय अधिक होने के बावजूद पूंजीगत व्यय सरकार की व्यय कार्यनीति का मुख्य आधार बना रहा। नतीजतन, पूंजीगत परिव्यय और राजस्व व्यय के बीच अनुपात (आरईसीओ) सुधरकर 2021-22 में 6.0 से 2022-23 (आरई) में 5.6 हो गया। इसी तरह, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच अनुपात 2021-22 में 5.4 से सुधरकर 2022-23 (संशोधित अनुमान) में 4.7 हो गया। कर राजस्व मजबूत रहा - वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और प्रत्यक्ष कर संग्रह के आधार पर सकल कर राजस्व बजट अनुमान से 2.9 लाख करोड़ रुपये अधिक रहा।

I.16 राज्य सरकारों ने 2022-23 के लिए सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.4 प्रतिशत पर रखने का अनुमान लगाया था । अनंतिम लेखे संकेत देते हैं कि राज्य सरकारों का वास्तविक प्रदर्शन बेहतर हो सकता है, जिसका कारण मुख्य रूप से केंद्र से अपेक्षा से अधिक कर अंतरण और राज्यों के अपने कर राजस्व में स्वस्थ वृद्धि का होना है। इसलिए 2022-23 के दौरान राज्यों का जीएफडी और जीडीपी के बीच अनुपात 3.0 प्रतिशत के भीतर रहने का अनुमान है। राजकोषीय क्षेत्र में, वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जारी पहला सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (एसजीआरबी) का पहला संस्करण जारी किया गया, जिसकी आय का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में किया जाएगा जिससे अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता कम होगी।

I.17 लंबे समय तक भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार में मंदी के बावजूद, भारत का व्यापारिक निर्यात 2022-23 के दौरान 450.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के रिकॉर्ड स्तर से 6.7 प्रतिशत अधिक है। भारत ने मोबाइल फोन और खिलौनों जैसे क्षेत्रों में शुद्ध आयातक से निर्यातक के रूप में बदलाव देखा और 'मेक इन इंडिया' और *'आत्मनिर्भर भारत'* जैसी नीतियों का लाभ उठाते हुए कम समय में रक्षा वस्तुओं के निर्यात में 10 गुना वृद्धि दर्ज की। वर्ष की पहली छमाही में उच्च वृद्धि दर्ज करने के बाद, भारत के व्यापारिक आयात में दूसरी छमाही के दौरान कमी आई, जो अन्य बातों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में गिरावट और निर्यात से संबंधित आयातों की धीमी मांग को परिलक्षित करता है। वर्ष के दौरान भारत का पण्य व्यापार घाटा बढ़ा, लेकिन दूसरी छमाही में बढ़ोतरी की गति धीमी हो गई।

I.18 वस्तु निर्यात के विपरीत, सेवा निर्यात में 27.9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि देखी गई, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं, व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन (बीपीएम) और इंजीनियरिंग अनुसंधान और डिजाइन (ईआर एंड डी) जैसे प्रमुख कार्यक्षेत्रों की सॉफ्टवेयर सेवाओं का प्रमुख योगदान रहा। इसके अलावा वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) में वृद्धि का लाभ भी हुआ।

I.19 पूंजी प्रवाहों के तहत, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शुद्ध अंतर्वाह 2022-23 के दौरान, यद्यपि वह मजबूत था, कमी आई और वह 28.0 बिलियन यूएस डॉलर रहा जबकि एक वर्ष पहले वह 38.6 बिलियन यूएस डॉलर था। इसके अलावा वर्ष के दौरान 5.9 बिलियन यूएस डॉलर का शुद्ध पोर्टफोलियो बहिर्वाह हुआ जो जोखिम से बचने के मनोभाव को परिलक्षित करता है जिसके कारण आस्तिवर्ग में ईएमई के प्रवाह प्रभावित हुए। 2022-23 में उधार की बढ़ती लागत ने पिछले वर्ष की तुलना में बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) को धन जुटाने के लिए कम आकर्षक बना दिया।

I.20 भारत की बाहरी कमजोरियों में संभावित वृद्धि की बाजार की आशंकाओं को दरकिनार करते हुए, भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी), हालांकि यह एक साल पहले 1.1 प्रतिशत से बढ़ा है, जीडीपी के 2.7 प्रतिशत (अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान) पर स्वीकार्य स्तर पर रहा। इन घटनाक्रमों के साथ-साथ, पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध पूंजी अंतर्वाह में कमी के कारण, अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान भुगतान संतुलन (बीओपी) के आधार पर विदेशी मुद्रा भंडार में 14.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आई। मूल्यांकन प्रभावों को शामिल किया जाए तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 2022-23 के दौरान 28.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई।

I.21 वर्ष के दौरान, बैंकिंग प्रणाली ने पूंजी बढ़ाने और आस्ति गुणवत्ता में सुधार के प्रयास जारी रखे। 2021-22 की दूसरी छमाही के बाद से एक नए ऋण चक्र की शुरुआत ने 2022-23 के दौरान गति पकड़ी, जिसके परिणामस्वरूप सभी प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करते हुए दोहरे अंकों की ऋण वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की आस्ति गुणवत्ता में सुधार जारी रहा। उनके सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात और निवल अनर्जक आस्ति (एनएनपीए) अनुपात में गिरावट आई और तिमाही गिरावट अनुपात कम हो गया। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में भी लगातार वृद्धि हुई। निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में सुधार देखा गया, जो बढ़ते ब्याज दर चक्र में जमा दरों की तुलना में उधार दरों के प्रति मौद्रिक नीति के उच्च स्तर के संचरण को परिलक्षित करता है। नतीजतन, कर के बाद लाभ (पीएटी) ने मजबूत वृद्धि दर्ज की। वर्ष के दौरान एससीबी के लिए इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) और आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) में और सुधार हुआ। कम स्लिपेज अनुपात, बाजार से पूंजी जुटाने और मुनाफे के माध्यम से निवल पूंजी अभिवृद्धि के साथ बैंकों को अपने पूंजी पर्याप्तता स्तर को मजबूत करने में मदद मिली और सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण किए जाने की आवश्यकता कम हुई। बढ़ती ब्याज दर के माहौल में बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के लिए ब्याज दर जोखिम सहनीय बना रहा, जिसे निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) जैसे समष्टिआर्थिक नीतिगत उपायों की सहायता हुई, जो बाज़ार मूल्य की तुलना में हुए नुकसान के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं।

I.22 आजादी के 75 वर्ष (*आजादी का अमृत महोत्सव*) मनाने के लिए, देश में बैंकिंग लेनदेन करने के डिजिटल तरीकों को अपनाने के लिए देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना की गई। इन 75 डीबीयू को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 16 अक्टूबर 2022 को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया गया। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार देश में 84 डीबीयू कार्यरत हैं।

I.23 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने 2022-23 के दौरान मजबूत ऋण वृद्धि बनाए रखी। इसके लिए उन्हें आर्थिक गतिविधि में व्यापक आधार वाले पुनरुद्धार और लक्षित नीतिगत पहलों की मदद हुई। इस क्षेत्र ने वर्ष के दौरान मजबूत बफर पूंजी, बेहतर आस्ति गुणवत्ता और तुलनपत्रों के समेकन के माध्यम से अपनी वित्तीय सुदृढ़ता को बेहतर किया। 2022-23 के दौरान एनबीएफसी के लिए पैमाना आधारित एक विनियामकीय ढांचा लागू किया गया।

I.24 वर्ष के दौरान, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा की गई ताकि उनके कॉर्पोरेट प्रशासन और विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत करने, उनके कामकाज की पारदर्शिता बढ़ाने और दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में उनकी भूमिका बढ़ाने के उद्देश्यों को हासिल किया जा सके। इसके अलावा, एक उत्तरदायी और अग्रगामी विनियामक दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में, क्रेडिट जोखिम बाजारों को मजबूत करने और विकसित करने, पूंजी पर्याप्तता और विनियमित संस्थाओं पर लागू प्रावधान ढांचे की मजबूती बढ़ाने और बैंक ऋण रेटिंग के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा अपनाई गई रेटिंग प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए। 6 अक्टूबर 2022 को रिज़र्व बैंक द्वारा एक नई सुपटेक पहल – *दक्ष* - रिज़र्व बैंक उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली शुरू की गई, जो एक वेब-आधारित एंड-टू-एंड वर्कफ़्लो एप्लिकेशन है जिसके माध्यम से रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के बीच अनुपालन संस्कृति को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से वास्तविक अनुपालन की अधिक केंद्रित तरीके से निगरानी करता है।

I.25 सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र में रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू किया और यूसीबी की वित्तीय सुदृढ़ता को मजबूत करने के उद्देश्य से विभेदित विनियामकीय तरीकों के साथ एक सरल चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे को अपनाया। इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के उपायों में सुदृढ़ यूसीबी के लिए और अधिक प्रचालनात्मक लचीलेपन की पेशकश करते हुए भी सहायता

प्रदान की जा रही है ताकि वे ऋण पहुंचाने में अपनी वांछित भूमिका को पूरा कर सकें।

I.26 केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित डिजिटलीकरण प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान चरणबद्ध तरीके से अपनी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पेश की, जिसमें क्रमशः 1 नवंबर 2022 और 1 दिसंबर 2022 को थोक और खुदरा क्षेत्रों में डिजिटल रुपये (e₹) के लिए प्राथमिक प्रयोग किए गए। इस प्रयोग से पहले सीबीडीसी के बारे में सामान्य रूप से और विशेष रूप से e₹ की नियोजित विशेषताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सीबीडीसी पर एक 'संकल्पना नोट' जारी किया गया।

I.27 भारत, महामारी के दौर मजबूत और अधिक लचीला बनकर उभरा है जिसमें आंशिक रूप से डिजिटल परिवर्तन की लहर का योगदान है। डिजिटल माध्यम से किए गए लेनदेन ने वर्ष 2022-23 में एक वर्ष पहले देखी गई मजबूत वृद्धि से भी अधिक उल्लेखनीय विस्तार दर्ज किया। 2022-23 में कुल डिजिटल भुगतान ने मात्रा और मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 57.8 प्रतिशत और 19.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष में क्रमशः 63.8 प्रतिशत और 23.1 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर थी। भारत ने 2022[2] में 46 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ वैश्विक स्तर पर तत्काल लेनदेन में सबसे बड़े भागीदार के रूप में उभरते हुए अन्य देशों को पीछे छोड़ दिया। व्यापारियों को तेजी से शामिल करने, बढ़ती डिजिटल जागरूकता और भुगतान प्रणाली के दायरे तथा पहुंच की दिशा में नीतिगत जोर से एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) की सघनता और विकास में तेजी आई।

I.28 2022-23 में *आधार* पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) में तेज वृद्धि देखी गई, जो देश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान के प्रसार को प्रमाणित करती है। डिजिटल हो रहे सरकारी नकद अंतरणों के माध्यम से हुआ सकारात्मक दबाव का भी इसमें आंशिक योगदान है। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में सुधार के साथ, कार्ड उद्योग ने खोई हुई गति हासिल की, जिसमें मासिक व्यय पूरे वर्ष में 1.6 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा।

I.29 रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान भुगतान विजन 2025 जारी किया, जिसका विषय है - ई-भुगतान सभी के लिए, सभी जगह, सभी समय - जिसमें सुरक्षित, भरोसेमंद, सुलभ, किफायती और कारगर भुगतान विकल्पों के साथ हर उपयोगकर्ता को सशक्त बनाने के लिए भारत की भुगतान प्रणालियों को और बेहतर बनाने का वादा किया गया है। प्रकार्यों को बेहतर बनाने और डिजिटल पथ पर उपभोक्ताओं को शामिल करने की दृष्टि से भुगतान प्रणालियों में विभिन्न सुधार किए गए। यूपीआई लाइट को ऑन-डिवाइस वॉलेट के माध्यम से यूपीआई का उपयोग करके ऑफ़लाइन मोड में छोटे मूल्य के लेनदेन की सुविधा के लिए शुरू किया गया। *रुपे* क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने की अनुमति दी गई ताकि भुगतान प्रसंस्करण के लिए जुड़े वित्तीय उत्पादों को व्यापक बनाकर उपयोग को बढ़ाया जा सके। यूपीआई में सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट की शुरुआत ने व्यापारिक भुगतान के लिए क्षमताओं को बढ़ाया। भारत में व्यापारिक भुगतान करने के लिए अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और विदेशी नागरिकों को भी यूपीआई सुविधा दी गई। सिंगापुर के *पे-नाऊ* के साथ यूपीआई को जोड़ने से दोनों देशों के बीच कम राशि के निधि अंतरण और विप्रेषण को सुविधाजनक बनाने में मदद मिली। *भारत बिल* भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के दायरे को सभी श्रेणियों के भुगतान और संग्रह को शामिल करने के लिए, आवर्ती और गैर-आवर्ती, दोनों स्वरूप के लिए विस्तारित किया गया। सीमा पार बिल भुगतान की सुविधा प्रदान करके अनिवासी भारतीयों को एक मानकीकृत बिल भुगतान सुविधा प्रदान करने के लिए भी बीबीपीएस का विस्तार किया गया।

[2] एसीआई वर्ल्डवाइड, रियल टाइम पेमेंट्स, ग्लोबल डाटा, 2023

I.30 सरकार के साथ-साथ रिज़र्व बैंक द्वारा देश में वित्तीय समावेशन को व्यापक और गहरा करने के लिए की गई पहल समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। रिज़र्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-इंडेक्स), जो 97 संकेतकों (जो पहुंच, उपलब्धता तथा उपयोग में आसानी, और सेवाओं की गुणवत्ता को दर्शाते हैं) के आधार पर वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रयासों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए एक मात्रात्मक पैमाना है, मार्च 2021 में 53.9 से बढ़कर मार्च 2022 में 56.4 हो गया (नवीनतम उपलब्ध), जिसमें सभी उप-सूचकांकों में वृद्धि देखी गई।

3. 2023-24 के लिए संभावनाएं

वैश्विक अर्थव्यवस्था

I.31 वैश्विक संवृद्धि 2023 में धीमी पड़ने की उम्मीद है और मध्यम अवधि में मंद रह सकती है। आईएमएफ के अप्रैल 2023 में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) के अनुसार 2023 के लिए वैश्विक वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत रहने की संभावना है जो मध्यावधि में 3.0 प्रतिशत पर स्थिर हो सकती है। वैश्विक स्तर पर, अवस्फीति के प्रयासों से एई के बीच हेडलाइन मुद्रास्फीति 7.3 प्रतिशत से घटकर 4.7 प्रतिशत और ईएमई के बीच 9.8 प्रतिशत से घटकर 8.6 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है। हालांकि, दृढ़ और ऊपरी ओर बढ़ने के दबाव के बीच यह प्रगति धीरे-धीरे होने की संभावना है। केंद्रीय बैंकों को बढ़ी अनिश्चितता के माहौल में मूल्य स्थिरता बहाल करने और संवृद्धि में मंदी को दूर करने के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उच्च ऋण स्तरों से संभावित वित्तीय जोखिम और अमेरिका और यूरोप में हाल के बैंकिंग क्षेत्र के घटनाक्रम वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अति प्रतिकूल प्रसार प्रभाव के साथ तनाव के अप्रत्याशित वृद्धि की गुंजाइश को उजागर करते हैं।

I.32 इक्विटी कीमतों के नुकसान की भरपाई हो जाने और बॉण्ड प्रतिफल में नरमी आने से वित्तीय बाजार वैश्विक मौद्रिक नीति के सख्त चक्र के संभावित अंत का संकेत दे रहे हैं। जिंसों की कीमतें भी नरम रुख के साथ कारोबार कर रही हैं क्योंकि वृद्धि में नरमी की आशंका बाजार धारणा पर हावी है। वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा नीतिगत सख्ती में नरमी बरतने से अमेरिकी डॉलर का अवमूल्यन हो सकता है जिससे अन्य एई और ईएमई मुद्राओं पर दबाव कम होगा, इसके बावजूद कि ईएमई में पूंजी प्रवाह के लिए दृष्टिकोण अनिश्चित बना हुआ है।

I.33 कुल मिलाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संभावनाएं उच्च मुद्रास्फीति, व्यापार, श्रम, पूंजी और प्रौद्योगिकी के संचलन पर प्रतिबंधों के माध्यम से संचालित भू-आर्थिक विभाजन के प्रतिकूल प्रभावों और वित्तीय क्षेत्र की कमजोरियों के बढ़ने की संभावनाओं से प्रभावित हैं। जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टो मुद्रा, फिनटेक और प्रौद्योगिकीय दुर्घटनाओं जैसी मध्यम से दीर्घकालिक चुनौतियां भी संभावित रूप से दृष्टिकोण को हानि पहुंचा सकती हैं।

I.34 इस पृष्ठभूमि में बहुपक्षीय सहयोग की तत्काल आवश्यकता जी20 को भारत की अध्यक्षता के तहत वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रभावी मंच बनाती है, जिसका विषय *'वसुधैव कुटुम्बकम'* – 'एक पृथ्वी', एक परिवार, एक भविष्य' है। वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार, और रिज़र्व बैंक एक साथ मिलकर ग्लोबल साउथ में उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) से संबंधित मुद्दों को फाइनान्स ट्रैक के दायरे में लाने के साथ-साथ पुराने मुद्दों को हल करने के लिए जी20 चर्चा का संचालन कर रहे हैं। जी20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों (एफएमसीबीजी), वित्त एवं केंद्रीय बैंक प्रतिनिधि (एफसीबीडी) और अध्यक्षीय प्राथमिकताओं और वितरण पर कार्य समूह की विभिन्न बैठकों[3] के तहत होने वाले विचार-विमर्श से इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित नीतिगत प्रतिक्रिया मिलेगी।

[3] 1 दिसंबर 2022 को जी20 अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद से बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

घरेलू अर्थव्यवस्था

I.35 घरेलू आर्थिक गतिविधियों को आने वाले समय में एक प्रेरणा रहित वैश्विक दृष्टिकोण की चुनौतियों का सामना करना है। लेकिन समुत्थानशील घरेलू समष्टिआर्थिक और वित्तीय स्थितियां, पिछले सुधारों से अपेक्षित लाभांश और वैश्विक भू-आर्थिक बदलावों से विकास के नए अवसर भारत को एक लाभप्रद स्थिति प्रदान करते हैं। वैश्विक स्तर पर जिंसों और खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी, *रबी* फसल की अच्छी संभावनाओं, संपर्क-गहन सेवाओं में निरंतर उछाल, पूंजीगत व्यय पर सरकार के निरंतर जोर, विनिर्माण में उच्च क्षमता उपयोग, दोहरे अंकों में ऋण वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति से क्रय शक्ति में कमी और व्यवसायों और उपभोक्ताओं के बीच बढ़ते आशावाद को ध्यान में रखते हुए, 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है जिसमें जोखिमों को समान रूप से संतुलित किया गया है।

I.36 वैश्विक जिंसों और खाद्य कीमतों में गिरावट और पिछले साल के उच्च इनपुट लागत दबाव कम होने के कारण मुद्रास्फीति जोखिम में कमी आई है। पिछले साल नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों की संचयी वृद्धि अवस्फीति प्रक्रिया को स्थिरता देगी और आपूर्ति पक्ष के उपाय खाद्य और ऊर्जा आघातों के कारण उभरे क्षणिक मांग-आपूर्ति असंतुलन को दूर करेंगे। स्थिर विनिमय दर और सामान्य मानसून रहने पर - जब तक *अल नीनो* घटना नहीं होती है- मुद्रास्फीति 2023-24 में नीचे जाने की उम्मीद है, जिसमें हेडलाइन मुद्रास्फीति पिछले साल दर्ज 6.7 प्रतिशत के औसत स्तर से घटकर 5.2 प्रतिशत हो जाएगी। मौद्रिक नीति यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजन को प्रगामी रूप से वापस लेने पर केंद्रित है कि संवृद्धि को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के आसपास रखा जाए।

I.37 रिज़र्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के मार्च 2023 दौर से पता चलता है कि उपभोक्ताओं द्वारा सामान्य आर्थिक स्थिति और घरेलू आय में आशावाद के कारण वर्तमान स्थिति में सुधार हुआ है। भविष्य की अपेक्षाएं भी सकारात्मक बनी हुई हैं। आने वाले वर्ष में गैर-आवश्यक वस्तुओं पर परिवारों का व्यय बढ़ने की उम्मीद है। तिमाही औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण के 101वें दौर के अनुसार विनिर्माण फर्म 2023-24 की दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही के लिए उत्पादन, ऑर्डर बुक, रोजगार की स्थिति और क्षमता उपयोग को लेकर सकारात्मक धारणा दिखा रही हैं। हाल ही में तिमाही सेवा और बुनियादी ढांचा परिदृश्य सर्वेक्षण के 36 वें दौर में, दोनों क्षेत्रों की निजी कंपनियों को लाभ मार्जिन और बिक्री कीमतों पर कम आशावाद के बावजूद 2023-24 की पहली तिमाही में रोजगार क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है। इनपुट लागत और बिक्री कीमतों में अपेक्षित वृद्धि के बावजूद ये फर्में 2023-24 की दूसरी और तीसरी तिमाही में समग्र व्यापार परिदृश्य में उच्च विश्वास दिखाती हैं।

I.38 वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का पुनर्गठन, हरित ऊर्जा की ओर पहल और चल रही तकनीकी प्रगति उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ निवेश गतिविधि में तेजी के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। कंपनियों और बैंकों के मजबूत तुलनपत्र और उच्च क्षमता उपयोग से निजी निवेश में गति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। बढ़ती ऋण वृद्धि, विशेष रूप से आवास और व्यक्तिगत ऋण, घरेलू पारिवारिक मांग में स्थिरता दर्शाता है। यह ग्रामीण और शहरी मांग के कई उच्च आवृत्ति संकेतकों, जैसे ट्रैक्टर और उर्वरक की बिक्री में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम भागीदारी दर में सुधार, घरेलू हवाई यात्री यातायात, यात्री वाहन बिक्री और मजबूत माल और सेवा कर संग्रह में भी परिलक्षित होता है। *रबी* की अच्छी फसल की उम्मीद और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में समुत्थानशीलता से उत्साहित मजबूत कृषि उत्पादन भी ग्रामीण मांग के लिए दृष्टिकोण को उज्ज्वल कर रहे हैं। निर्माण गतिविधि की रफ्तार बनी रहने रखने की संभावना है जैसा कि इसके समीपवर्ती संकेतकों : इस्पात की खपत और सीमेंट उत्पादन, में स्थिर विस्तार से परिलक्षित होता है। पोर्ट कार्गो ट्रैफिक और रेलवे फ्रेट ट्रैफिक आवागमन भी, इनपुट लागत दबाव में धीरे-धीरे कमी के बीच, औद्योगिक गतिविधि में तेजी की ओर इशारा करते हैं।

I.39 *खरीफ* फसल की संभावनाएं दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा की प्रगति पर निर्भर करेंगी। मौसम विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के अनुसार जून-सितंबर 2023 के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम की बारिश दीर्घकालिक औसत (एलपीए) के 96 प्रतिशत (+/- 4) पर सामान्य होने की संभावना है। हालांकि, दक्षिण-पश्चिम मानसून बारिश का वास्तविक प्रदर्शन *अल नीनो* घटना के कारण संभावित वर्षा की कमी और सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुवीय के प्रतिसंतुलन प्रभावों के परस्पर प्रभाव पर निर्भर करेगा। बुवाई का मौसम शुरू होने से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा किसानों को बुवाई के रकबे का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सरकार ने 2023-24 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 332 मिलियन टन रखा है, जो पिछले साल के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान से 0.4 प्रतिशत अधिक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा 2023 को मिलेट अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित करने के साथ, भारत मोटे अनाज की निर्यात क्षमता को बढ़ा सकता है, क्योंकि वर्तमान में कुल मिलेट उत्पादन का केवल एक प्रतिशत निर्यात किया जाता है।

I.40 हाल के वर्षों में सरकार के पूंजीगत व्यय में निरंतर वृद्धि के प्रभावों से 2023-24 में उच्च निजी निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट 2023-24 में, बजटीय पूंजीगत व्यय में 37.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत परिव्यय प्राप्त हुआ है। पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण के लिए आबंटन भी पिछले वर्ष के 1.0 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.3 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। ऋण की पूरी राशि 2023-24 में खर्च की जानी है और इन ऋणों का एक हिस्सा राज्यों द्वारा अपने वास्तविक पूंजीगत व्यय को बढ़ाने पर निर्भर करेगा। पूंजीगत व्यय के लिए उच्च आबंटन के अलावा, केंद्रीय बजट 2023-24 में कई उपायों की घोषणा की गई है, जिससे विकास की गति को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जैसे; संबद्ध क्षेत्रों का विविधीकरण और संवर्धन; अंतिम स्थान तक संपर्क के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना; निर्यात संवर्धन; सहकारिता आधारित विकास; डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से कृषि विस्तार सेवाओं को मजबूत करना; और कृषि-स्टार्टअप के माध्यम से निजी निवेश को बढ़ावा देना। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से निजी निवेश वृद्धि भी मजबूत होने की उम्मीद है जिससे अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री *गति शक्ति* और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति (एनएलपी) के तहत लॉजिस्टिक्स दक्षता और लागत प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए उठाए गये कदमों से लॉजिस्टिक लागत में कमी आने की उम्मीद है।

I.41 वर्ष 2023-24 में सेवा क्षेत्र की संभावना अनुकूल बनी हुई है। महामारी के बाद स्थावर संपदा और विनिर्माण क्षेत्र ने पूर्व स्थिति प्राप्त की है और आने वाले वर्ष में भी वह अच्छा प्रदर्शन करेगा ऐसी संभावना है क्योंकि आवास के लिए मांग और आपूर्ति, दोनों ही तेजी पर हैं।

I.42 सेवा निर्यात के मजबूत रहने और आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में नरमी का प्रभाव रहने से बाह्य क्षेत्र में चालू खाता घाटा (सीएडी) कम रहने की उम्मीद है। वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह अस्थिर रह सकता है। हालांकि अनुकूल घरेलू संवृद्धि परिदृश्य, कम मुद्रास्फीति और कारोबार अनुकूल नीतिगत सुधारों से अस्थिर एफडीआई प्रवाह स्थिति में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, खाड़ी देशों में बेहतर विकास संभावनाओं के कारण आवक विप्रेषण मजबूत रहने की संभावना है। परिणामत:, 2023-24 के दौरान बाह्य संवेदनशीलता संबंधी जोखिम और भी कम हो सकता है। 31 मार्च 2023 को घोषित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 तुलनात्मक लाभ को पोषित करने के लिए निर्यात-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने का प्रयास करती है; भारत को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (जीवीसी) में भाग लेने और बाजारों तक पहुंच का विस्तार करने में मदद करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में अवसरों के उपयोग अवसर प्रदान करती है; और भारतीय रुपये (आईएनआर) में अधिक व्यापार की

संभावनाओं को खोजती है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का अनुमान है कि वैश्विक व्यापार के परिमाण में वृद्धि वर्ष 2022 के 2.7 प्रतिशत से घटकर 2023 में 1.7 प्रतिशत हो जाएगी। ऐसे में एफटीपी में सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति आवश्यक होगी।

I.43 अमेरिका और यूरोप में वित्तीय क्षेत्र की हाल की उथल-पुथल ने मौद्रिक नीति सख्ती के संदर्भ में वित्तीय स्थिरता और वित्तीय संस्थानों की तदनुसार समुत्थानशीलता संबंधी जोखिमों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता को जरूरी बना दिया है। यद्यपि भारतीय बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं मजबूत और समुत्थानशील बने हुए हैं, उन्हें इन नए आघातों के लिए दबाव परीक्षण करने की आवश्यकता है। इसलिए पूंजी बफर और चलनिधि स्थिति की लगातार समीक्षा और सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए। तदनुसार, 2023-24 के दौरान प्रावधान के लिए अपेक्षित हानि-आधारित दृष्टिकोण की शुरूआत पर दिशानिर्देश जैसे नीतिगत उपायों की घोषणा किए जाने की संभावना है। इसके अलावा, समाधान परितंत्र को अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान दबाव वाली आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने और विवेकपूर्ण ढांचे (कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के संबंध में दबाव के समाधान पर दिशानिर्देशों सहित) की व्यापक समीक्षा किए जाने की भी संभावना है।

I.44 2023-24 के दौरान, रिज़र्व बैंक का लक्ष्य विभिन्न उपयोग मामलों और विशेषताओं को शामिल करके सीबीडीसी-खुदरा और सीबीडीसी-थोक में चल रहे पायलट प्रयोगों का विस्तार करना है। सीबीडीसी-रिटेल में प्रायोगिक परियोजना को और अधिक स्थानों पर विस्तारित करने और प्रतिभागी बैंकों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है।

I.45 जैसा कि रिज़र्व बैंक भुगतान विजन 2025 को साकार करने की ओर बढ़ रहा है। बढ़ी हुई पहुंच, ग्राहक केंद्रीयता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में अब तक उठाए गए कदमों को अखंडता, समावेश, नवोन्मेष, संस्थागतकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण के पांच स्तंभों के माध्यम से अधिक समेकित और निर्मित किया जाएगा। इन उपायों से भारत की भुगतान प्रणालियों को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आगे चलकर, नवोन्मेष और ग्राहक संरक्षण पर निरंतर ध्यान देने के साथ, प्रमुख प्राथमिकताएं समावेश और अंतरराष्ट्रीयकरण होंगी। बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों से भुगतान की सुविधा के लिए यूपीआई का दायरा बढ़ाया जाएगा। चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) को मौजूदा तीन क्षेत्रीय ग्रिडों से "वन नेशन वन ग्रिड" में स्थानांतरित करने की योजना है। रिज़र्व बैंक सीमा पार भुगतान और विप्रेषण के लिए भुगतान प्रणालियों की पहुंच बढ़ाने की परिकल्पना करता है। सिंगापुर के साथ यूपीआई-पे-नाऊ लिंकेज की तर्ज पर अन्य अधिकार-क्षेत्रों में त्वरित भुगतान प्रणालियों के साथ जुड़ाव प्रक्रियाधीन है।

I.46 वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) के लक्ष्यों में से एक है मार्च 2024 तक देश के प्रत्येक ब्लॉक में वित्तीय साक्षरता केंद्रों (सीएफएल) की पहुंच का विस्तार करना। अगले प्रयासों के रूप में सीएफएल की पहुंच को अब चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बढ़ाया जा रहा है, और 2024 तक पूरे देश को शामिल किए जाने की उम्मीद है।

I.47 वित्तीय प्रणाली में जनता का विश्वास सुनिश्चित करने और विनियमित संस्थाओं (आरई) के ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए, रिज़र्व बैंक अपनी 24x7 ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) में कृत्रिम मेधा (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल) और अन्य अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों को जोड़ने की प्रक्रिया में है ताकि शिकायतों को आसानी से दर्ज किया जा सके, शिकायतकर्ताओं को शिकायत निवारण पर आवश्यक जानकारी प्रदान की जा सके और लोकपाल के लिए निर्णय लेने में सहायता करके शिकायत निपटान में तेजी लाई जा सके।

4. निष्कर्ष

I.48 संक्षेप में, आघातों ने 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की समुत्थानशीलता की परीक्षा ली। मजबूत समष्टिआर्थिक नीतियों, जिंसों की कीमतों में नरमी, मजबूत वित्तीय क्षेत्र, स्वस्थ कॉर्पोरेट क्षेत्र, सरकारी व्यय की गुणवत्ता पर निरंतर राजकोषीय नीतिगत जोर और आपूर्ति शृंखलाओं के वैश्विक पुनर्गठन से उपजी वृद्धि के नए अवसरों के कारण मुद्रास्फीतिक दबाव कम होने के माहौल में 2023-24 में भारत की संवृद्धि की गति बरकरार रहने की संभावना है। तथापि, मंथर होती वैश्विक संवृद्धि लंबे समय तक भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में नए दबाव की घटनाओं के बाद वित्तीय बाजार में अस्थिरता का संभावित उछाल संवृद्धि के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा कर सकता है। इसलिए, भारत की मध्यम अवधि की संवृद्धि क्षमता में सुधार के लिए संरचनात्मक सुधारों को बनाए रखना जरूरी है।